(b) whether Government are aware that due to acute shortage of these essential commodities at the PDS centres, there were communal tensions and of Law and Order problem in the State;

(c) whether there is any disparity in allocation of these commodities in Metropolitan cities and rural areas; and

(d) if so, the extent thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The total quantities of rice, wheat, imported edible oil and Kerosene allotted to Maharashtra for supply through the Public Distribution System during 1991 (January-August, 1991) is as under:

(*in thousand tonnes*)

Rice . . .	367.0
Wheat . . .	920.0
Imported Edible Oil	10.6
Kerosene Oil . .	970.0

The average demand per month of wheat and rice during the period above is about 1.36 lakh tonnes and 0.59 lakh tonnes respectively. The annual demand for imported edible oil for oil-year 1990-91 was 1.68 lakh tonnes.

(b) Government has not received any such report from the State Government.

(c) Allocations of PDS items are made to the State Governments/U.T. Administrations as a whole and further internal distribution within the State, including rural and urban areas, are decided by the the concerned State Governments/UT Administrations.

Allocations from Central Pool are supplemental in nature and are not meant to meet the entire requirements of the State Governments/UT Administraions.

566. [*Transferred to 13th Sept.*, 1991]

Arun Singh Committee Report on Indian Defence Forces

567. SHRI A. G. KULKARNI:
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken in the light of Arun Singh Committee Report to up-date technologically the Indian Defence forces; and

(b) whether the neighbours who have cated armaments in their holdings, the other sophisticated armaments can be matched with indigenously manufactured space missiles and similar armaments in destructive power?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) The Arun Singh Committee recommendations relate primarily to measures for achieving economy and securing optimal utilisation of available resources and do not deal specifically with the issue of technological upgradation of the Indian Defence Forces.

(b) With the missiles and other sophisticated armaments in their holdings, the Defence Forces of the country are fully capable of countering any threat from potential adversaries in our neighbourhood.

उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता में प्रस्तावित 40% कटौती को वापस लिया जाना

568. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे तथा मंझोले किसानों को उर्वरकों

पर दी जा रही राज सहायता में प्रस्तावित 40 प्रतिशत की कटौती वापस ले ली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़े किसानों के लिए यह कटौती घटाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग ने इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु कोई उपाय सुझाए हैं, कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) सरकार ने उर्वरकों के मूल्य में औसतन 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी जो 25-7-91 से लागू हुई । तत्पश्चात् पहले के 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी के स्थान पर बढ़ोतरी को औसतन 30 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया । ये संशोधित मूल्य 14-8-91 से लागू हुए । ऐसा करते हुए सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि छोटे और सीमान्त किसानों का मूल्य वृद्धि के प्रभाव से मुक्त रखा जायेगा और उन्हें 25-7-91 से पहले के मूल्य पर उर्वरकों की आपूर्ति की जायेगी ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से दिशा निर्देश तैयार किये हैं जिसके अनुसार राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को योजनायें बनाने का सुझाव दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे और सामान्त किसान 25-7-91 के पहले के मूल्य पर उर्वरक प्राप्त करें । इन दिशा/निर्देशों को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिया गया है जो उपयुक्त योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है ।

सस्ती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता

569. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छोटे तथा सीमांत किसानों को सस्ते पर उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्ण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र शा प्रदेशों तथा पंजाब के किसानों को स दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन विक्रय के पर सस्ती दरों पर बेचे जाने के उर्वरकों की कुल कितनी वार्षिक म भेजे जाने की योजना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में र मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) (से (ग) राज्य सरकारों को सलाह गई है कि वे एक ऐसी योजना बन जिसके अनुसार छोटे और सीमान्तर किसानों को उर्वरकों में अद्यतन वृ छूट दी जाएगी । इस योजना के नि पोषण के लिए 405 करोड़ रुपये राशि अलग रखी गई है और उसे रा को आवंटित किया गया है । इसमें पंजाब को 9.016 करोड़ रुपये आवं किये गये हैं ।

Indigenisation in IAF

570. KUMARI ALIA:
SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of DEFENCE pleased to state:

(a) whether Government have seen Press interview in which the former Chief Marshal S. K. Mehra asserted t if we do not commit ourselves to ind nisation, the Indian Air Force wo cease to exist after the turn of centu if so, what is Government's reaction the to; and

(b) what are Government's plans indigenisation in Indian Air Force the progress made in this field so far

THE MINISTER OF DEFEN (SHRI SHARAD PAWAR): (a) (b) A statement is enclosed.